

अध्याय III

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

परिचय

3.1 मार्च 2016 के अंत की स्थिति में, भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण संस्थानों सहित 1,574 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा 93,913 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान आते हैं (चार्ट 3.1)। 2015-16 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र की वृद्धि मंद हुई। उनके लाभप्रदता सूचकों एवं आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट देखी गई। 2014-15 के दौरान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को छोड़कर अल्पावधि ग्रामीण सहकारी समितियों के तुलन पत्र की वृद्धि में मंदी आई जबकि दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी समितियों के तुलन पत्र में तेजी देखी गई। इसके साथ ही, अधिकांश ग्रामीण सहकारी समितियों के निवल लाभ में कमी होने के बावजूद सभी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ।

शहरी सहकारी बैंक

3.2 2016 में, शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 1,574 रह गई जो 2015 में 1,579 थी। बहु-राज्यी शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 29 से बढ़कर 31 हो गई, किंतु गैर-अनुसूचित एकल-राज्यी शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1,507 से घटकर मार्च 2016 के अंत में 1,502 रह गई (चार्ट 3.1)।

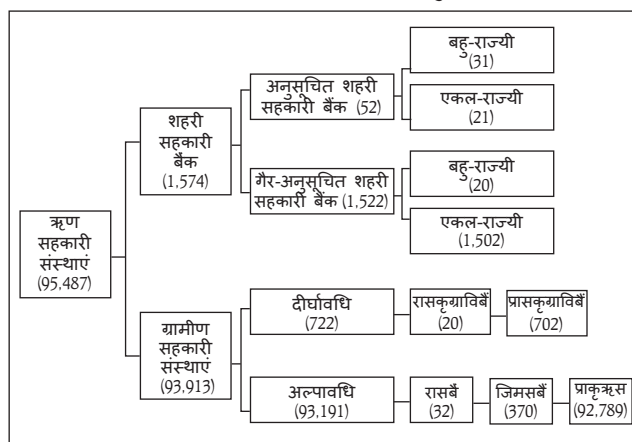
तुलन-पत्र से आय-व्यय

3.3 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में मंदी जारी रही। 2014-15 की 11.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में घटकर यह 2015-16 में 9.9 प्रतिशत रह गई (चार्ट 3.2)। आस्ति पक्ष में, ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि 9.2 प्रतिशत की दर से हुई जो 2014-15 में हुई 11.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम रही। देयता पक्ष में, जमाराशियों एवं आरक्षित निधियों तथा अतिरेक राशि का उपचय अपेक्षाकृत निम्न दरों पर हुआ (क्रमशः 10.4 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत रहा जबकि 2014-15 में ये दरें क्रमशः 11.8 प्रतिशत एवं 7.4 प्रतिशत थीं)।

लाभप्रदता

3.4 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों के इक्विटी एवं आस्तियों पर प्रतिलाभ में कमी देखी गई। निवल ब्याज

चार्ट 3.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थानों की संरचना
(31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)



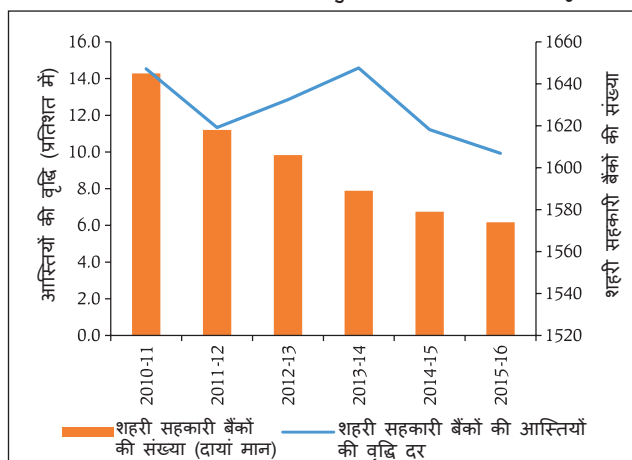
एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंकों; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े, शहरी सहकारी बैंकों के मामले में - मार्च 2016 के अंत में संस्थानों की संख्या और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के मामले में - मार्च 2015 के अंत में संस्थानों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं।

2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के मामले में, सहकारी संस्थाओं की संख्या रिपोर्ट करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

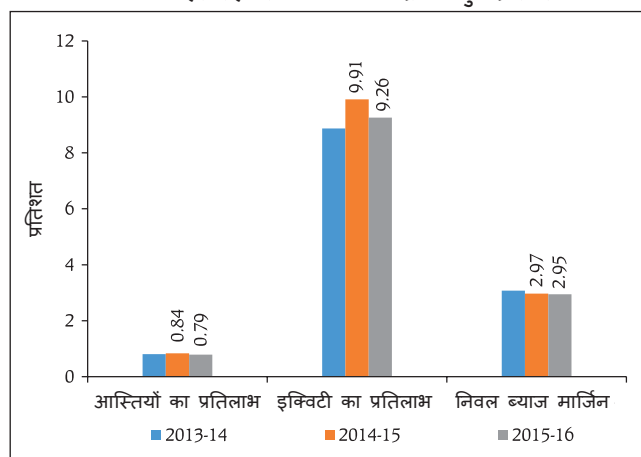
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट 3.2 : शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या और आस्तियों में वृद्धि



टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 3.3 : शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक


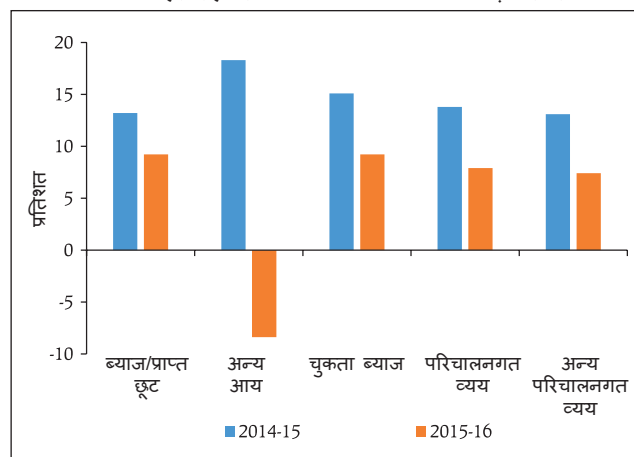
टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

मार्जिन में कमी जारी रही (चार्ट 3.3)। 2014-15 के रुझान को जारी रखते हुए, उनके कुल व्यय (8.8 प्रतिशत) में उनकी कुल आय (7.9 प्रतिशत) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 2015-16 के दौरान जोखिमों/आकस्मिकताओं के लिए गए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक रहे। शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में कमी आई। ब्याज से होने वाली आय में कमी जारी रही और 2015-16 में यह 9.2 प्रतिशत रही जबकि 2014-15 में यह 13.2 प्रतिशत थी। इनके अलावा, 2015-16 में अन्य आय में 8.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जबकि 2014-15 में इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (चार्ट 3.4)।

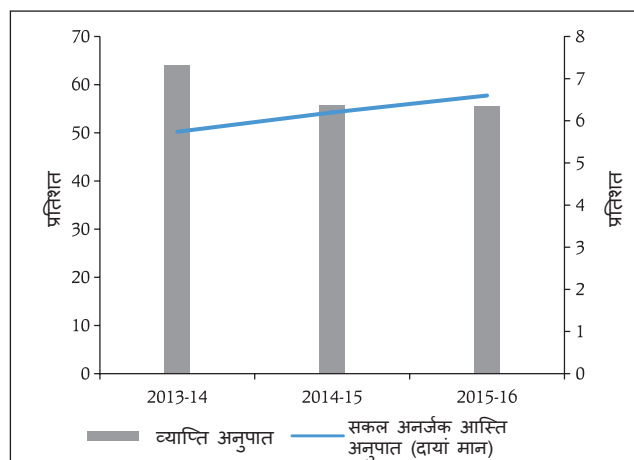
आस्ति गुणवत्ता

3.5 शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में आस्तियों की तुलना में अधिक दर से वृद्धि जारी रही। मार्च 2016 के अंत में, सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 6.6 प्रतिशत रहा जबकि मार्च 2015 के अंत में यह अनुपात 6.2 प्रतिशत था (चार्ट 3.5)। 2014-15 के दौरान प्रावधानों में सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप व्याप्ति अनुपात 2013-14 में रहे 63.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर 55.8 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट 2015-16 के दौरान प्रावधानों में हुई वृद्धि के अनुरूप रही। इसके कारण व्याप्ति अनुपात को 55.5 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रखा जा सका (चार्ट 3.6)।

चार्ट 3.4 : शहरी सहकारी बैंकों के आय एवं व्यय - घटबढ़ प्रतिशत में


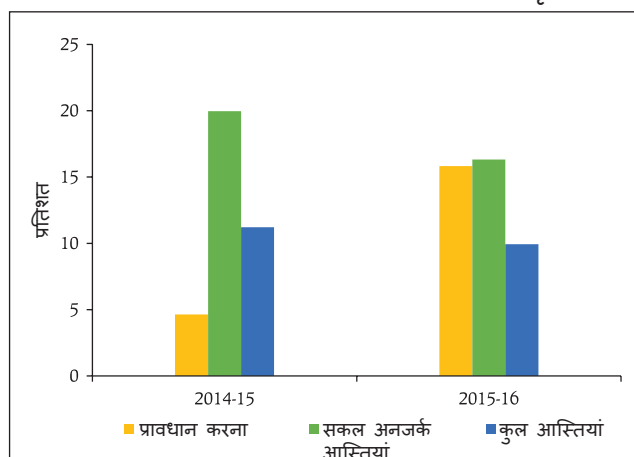
टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.5 : शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां


टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं।

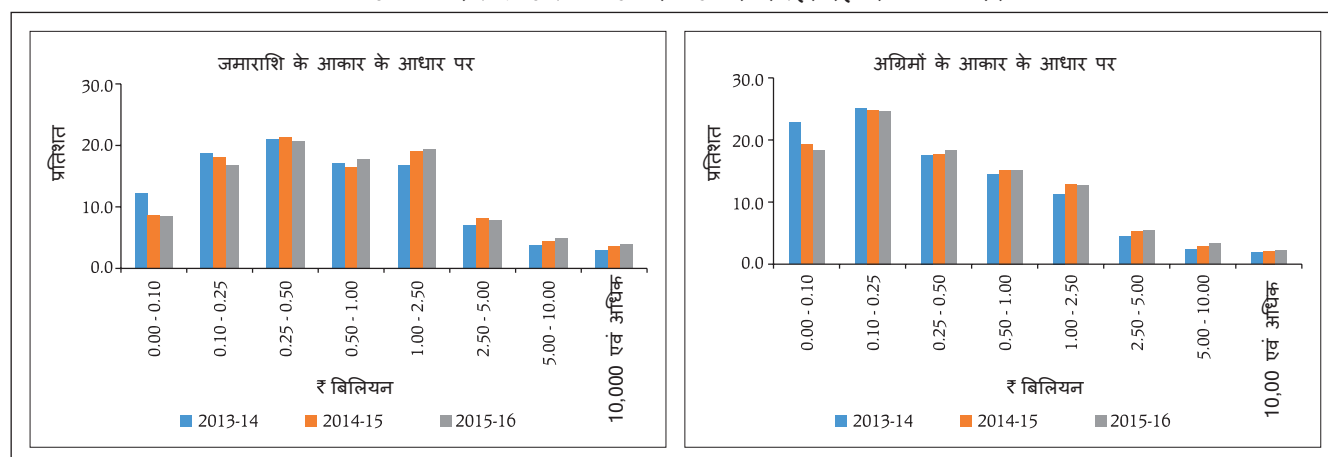
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.6 : आस्तियों, अनर्जक आस्तियों एवं प्रावधानों में वृद्धि


टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.7 : जमाराशि एवं अग्रिमों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण



टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति
2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

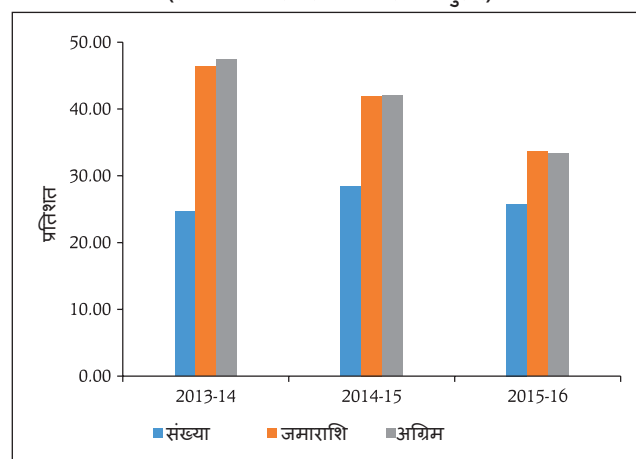
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां

3.6 टियर-II के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों¹ की संख्या में वृद्धि जारी रही (मार्च 2013 के अंत में 412 थी जो बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 442 हुई और उसके बाद मार्च 2015 में 447 हुई)। 2015-16 में, सामान्यतः, जिन शहरी सहकारी बैंकों के पास बड़ी मात्रा में जमा राशि और अग्रिम धारित थे, उनमें वृद्धि जारी रही (चार्ट 3.7)।

3.7 सीएएमईएलएस (कैमल्स) मॉडल के अंतर्गत उच्चतम श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों² का हिस्सा 2014-15 के 28.4 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2015-16 में 25.8 प्रतिशत रह गया। इस श्रेणी के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार के हिस्से में भी तेजी से गिरावट आई, जो अपेक्षाकृत बड़े शहरी सहकारी बैंकों में बढ़ते जोखिम को दर्शाता है (चार्ट 3.8)।

चार्ट 3.8 : ए श्रेणी की रेटिंग में शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा (संख्या एवं कारोबार के आकार के अनुसार)



टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति
2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

¹ टिअर-II के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें -

- किसी एक जिले में परिचालनगत बैंक में जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो।
 - एक से अधिक जिलों में परिचालनगत बैंक में जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो, बशर्ते बैंक की शाखाएं निकटवर्ती जिलों में कार्यरत रही हों, और एक जिले में स्थित शाखाओं की जमाराशियों और अग्रिमों का अलग से हिस्सा बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95 प्रतिशत हो।
 - जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो, जिन बैंकों की शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में स्थित रहीं हों किंतु बाद में जिला के पुनर्परिीसन किए जाने के कारण वह बहु-जिला स्थित बैंक हो गया हो।
- अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टिअर-II के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।

3.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के रुझान के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि की तुलना में ऋण अनुपात में थोड़ी कमी आई। 2015-16 में यह अनुपात घटकर 62.5 प्रतिशत रह गया, जो 2014-15 में 63.2 प्रतिशत था। जमाराशि की तुलना में निवेश अनुपात 2015-16 में घटकर 30.8 प्रतिशत रह गया जो 2014-15 में 34.7 प्रतिशत था। 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया क्योंकि मध्यवर्ती/राज्य सहकारी बैंकों के पास धारित शेष राशि को एसएलआर निवेश के रूप में मान्यता दिया जाना 01 अप्रैल 2015 से बंद कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश' की वृद्धि दर में सुधार हुआ। 2015-16 में बढ़कर यह दर 13 प्रतिशत हो गई, जो 2014-15 में 7.3 प्रतिशत थी (चार्ट 3.9)। असमग्र स्तर पर देखा जाए तो गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर यह प्रभाव अधिक जोर का पड़ा क्योंकि ये बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में निवेश का अधिक हिस्सा मध्यवर्ती/राज्य सहकारी बैंकों में रखे हुए थे।

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया जाना

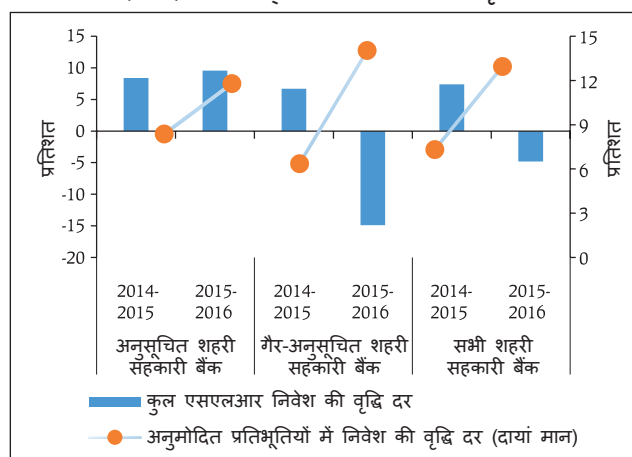
3.9 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विकास एवं अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडीआरबीटी) से विचार-विमर्श करते हुए अप्रैल 2016 से, कोर बैंकिंग समाधान को लागू करने में संसाधनों की कमी का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों की मदद करने की योजना तैयार की है। यह योजना बैंकिंग विकास एवं अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान / भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) के माध्यम से लागू की जा रही है। जिन शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग सुविधा को अभी लागू नहीं किया है अथवा इसे आंशिक रूप से लागू किया है, उनको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना को शहरी सहकारी बैंकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित रुझान

3.10 मार्च 2016 के अंत में, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 52 थी (मार्च 2015 के अंत में 50 थी) 2015-16 में सभी शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों में इनके हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट 3.10)।

3.11 2015-16 में, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की तुलना पिछले वर्ष हुई वृद्धि से की जा सकती है। वर्ष के दौरान, शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के विस्तार में जमाराशि, ऋणों तथा अग्रिमों का प्रमुख हिस्से के रूप में योगदान जारी रहा।

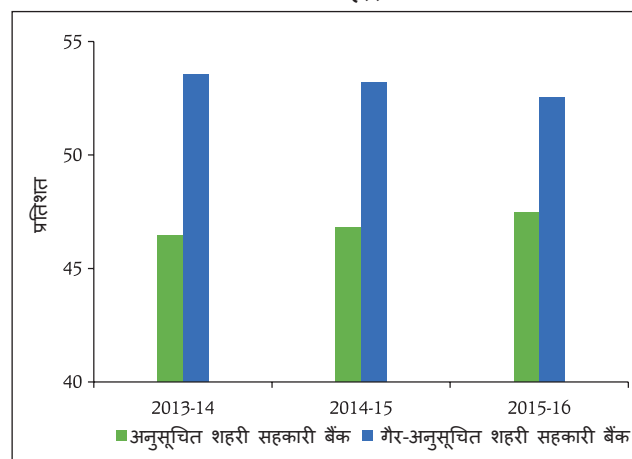
चार्ट 3.9 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एसएलआर निवेश की वृद्धि दर में परिवर्तन



टिप्पणी : 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियाँ और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.10 : कुल आस्तियों में अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा



टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति

2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियाँ और स्टॉफ की गणनाएं

3.12 2015-16 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता सूचकों ने स्थिति बिगड़ने का संकेत दिया। इक्विटी के प्रतिलाभ एवं आस्तियों के प्रतिलाभ दोनों में गिरावट आई, जबकि निवल ब्याज मार्जिन में थोड़ी वृद्धि हुई (चार्ट 3.11)। गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के विपरीत व्यय में वृद्धि, आय वृद्धि से अधिक बनी रही। 2015-16 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ मार्जिन के स्तर में गिरावट आई।

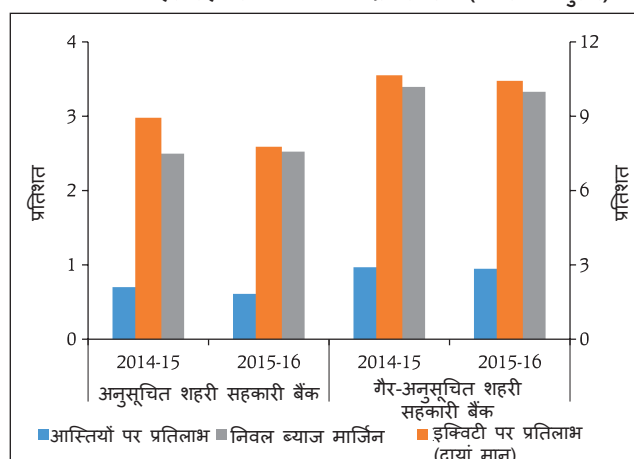
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

3.13 2015-16 में, लघु उद्यमियों एवं आवास क्षेत्र को दिए गए ऋण में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा (चार्ट 3.12)। कमजोर तबकों के प्रति लक्षित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के हिस्से में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। ऐसा विशेषरूप से 2014-15 एवं 2015-16 के बीच सूक्ष्म, लघु उद्यमों तथा आवास क्षेत्रों में हुआ (चार्ट 3.13)।

ग्रामीण सहकारी बैंक

3.14 2014-15 में, प्राथमिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों (अल्पावधि एवं दीर्घावधि -दोनों) की संख्या कम हुई, जिसके कारण ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या घटकर 93,913 रह गई जो 2013-14 में 94,718 थी। मार्च 2015 के अंत में, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कुल आस्तियों में अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं, जिसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती

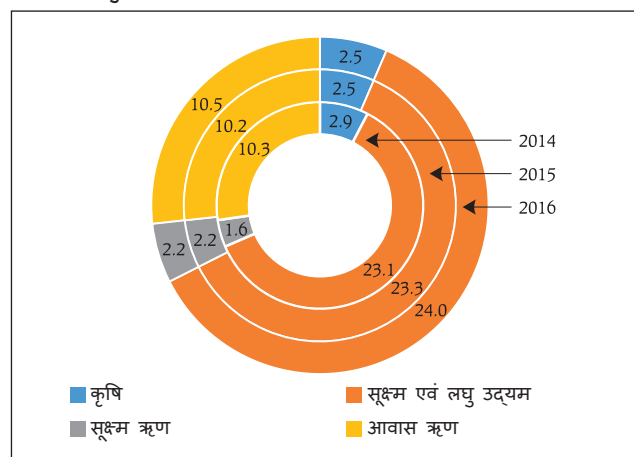
चार्ट 3.11 : शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता संकेतक (प्रकार के अनुसार)



टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

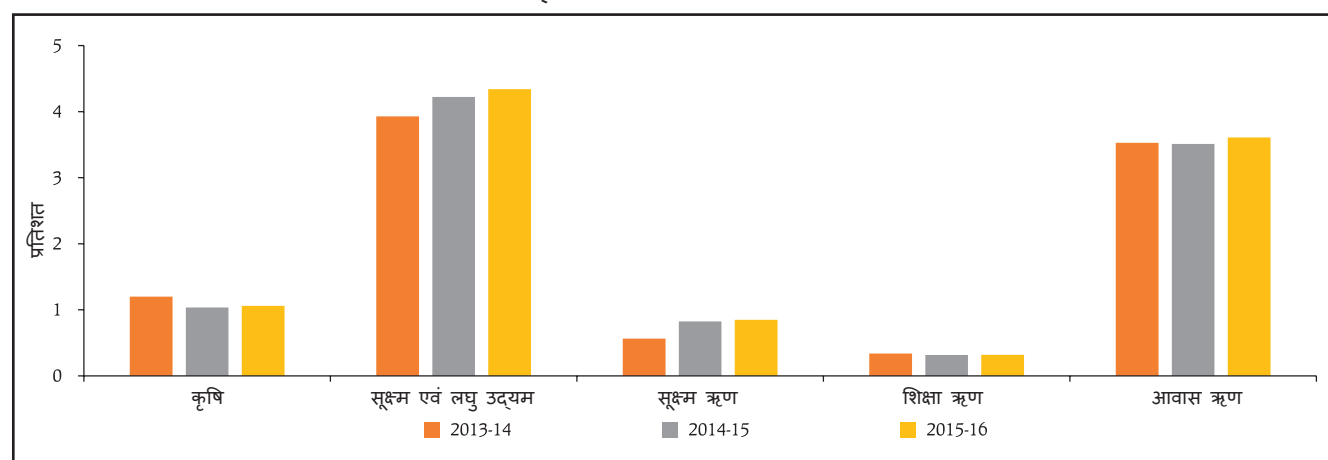
चार्ट 3.12 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में चुनिंदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण का वितरण



टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.13 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त कमजोर तबकों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत



टिप्पणी : 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

सारणी 3.1 : ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की रूपरेखा (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

(₹ बिलियन)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी बैंकों की संख्या	32	370	92789	20@	702
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधि (पूँजी + आरक्षित निधि)	141.8	293.7	216.8	74.7	53.5
ii. जमाराशि	1028.1	2588.1	846.2	18.4	10.2
iii. उधारराशि	687.3	800.0	999.8	161.1	163.7
iv. ऋण एवं अग्रिम	1145.5	2194.0	1472.3*	211.9	148.1
v. कुल देयता/आस्तियां	1988.6	4076.9	2237.1+	332.9	306.8
इ. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान #					
क. संख्या	28	304	43653	9	319
ख. लाभ की राशि	11.1	18.3	28.3	1.1	1.8
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
क. संख्या	4	58	37440	4	381
ख. लाभ की राशि	0.3	10.5	43.8	5.0	5.6
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	10.8	7.8	(-)15.5	(-) 3.9	(-) 3.8
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	57.2	208	357.9++	64.4	53.6
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	5.0	9.5	24.3	30.3	36.2
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली अनुपात (प्रतिशत)	94.9	77.3	उन	46.7	44.6

टिप्पणी: @ इन संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार है - 9 लाभ में रहे, 4 (हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुच्चेरी एवं त्रिपुरा) हानि में रहे, 3 (असम, बिहार, ओरिसा) ने कार्यशील नहीं हैं/निष्क्रिय हैं, एक (मणिपुर) समाप्त हो चुकी है, दो (मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र) परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन हैं, और छत्तीसगढ़ में एलटी संरचना को एसटी संरचना में मिला दिया गया है। # 362 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, * बकाया ऋण एवं अग्रिम, + कार्यशील पूँजी, ++ कुल बकाया राशि, उन = उपलब्ध नहीं

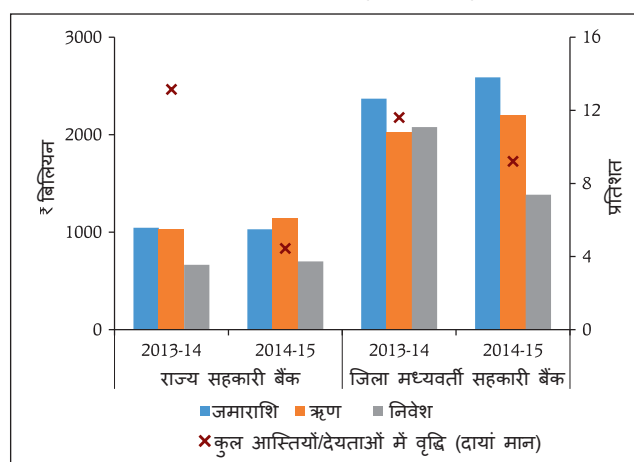
सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) आती हैं; का हिस्सा का लगभग 93 प्रतिशत रहा (सारणी 3.1)।

अल्पावधि ग्रामीण ऋण संस्थान - राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

3.15 राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र की वृद्धि में मंदी आई। 2013-14 में इनकी वृद्धि 13.1 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो 2014-15 में घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई (चार्ट 3.14)। ऐसा प्राथमिक रूप से जमा राशि की वृद्धि में मंदी होने, 'अन्य देयता' के हिस्से की वृद्धि में स्पष्टरूप से मंदी आने, नकदी एवं बैंक खाते में शेष राशि और आस्ति पक्ष में ऋणों एवं अग्रिमों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि होने के कारण हुआ।

3.16 राज्य सहकारी बैंकों की आय वृद्धि में मंदी आई। यह आय 2013-14 में 9.7 प्रतिशत थी जो 2014-15 में घटकर 5.6 प्रतिशत रह गई। मंदी का कारण ब्याज से होने वाली आय वृद्धि में मंदी होना रहा। 2014-15 में परिचालनात्मक खर्चों में तेजी से वृद्धि (9.3 प्रतिशत) होने के बावजूद व्यय वृद्धि में कमी आई। यह वृद्धि 2013-14 में 12.9 प्रतिशत थी जो 2014-15 में घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई। ऐसा, 2014-15 में व्यय के हिस्से के रूप में 'प्रावधानों तथा आकस्मिक

चार्ट 3.14 : राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के चुनिंदा संकेतक



स्रोत: नाबार्ड

निधियों' के 19.9 प्रतिशत कम रहने (2013-14 में 42.6 प्रतिशत अधिक होने की तुलना में) के कारण हुआ। प्रावधानों एवं आकस्मिकता निधियों के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर होने से 2014-15 के दौरान निवल लाभ में 29.9 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 में इसमें 24.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

3.17 2014-15 में, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के तुलन पत्रों में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी (2012-13 में 13.3 प्रतिशत और 2013-14 में 11.6 प्रतिशत)। देयता पक्ष से अन्य देयताओं तथा जमाराशियों के योगदान में कमी आई जबकि आस्ति पक्ष से ऋणों एवं अग्रिमों की अपेक्षाकृत कम वृद्धि और निवेश में ऋणात्मक वृद्धि होने के कारण मंदी आई।

3.18 2014-15 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 49.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में 0.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ब्याज से होने वाले आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के कारण 2014-15 में आय में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दूसरी तरफ, व्यय के हिस्से के रूप में 'प्रावधानों एवं आकस्मिक निधियों' में तेजी से वृद्धि (2014-15 में 26.8 प्रतिशत बनाम 2013-14 में (-)22.4 प्रतिशत) होने के कारण व्यय बढ़कर 2014-15 में 12.2 प्रतिशत हो गया जो 2013-14 में 11.1 प्रतिशत हो गया।

3.19 राज्य सहकारी बैंकों ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की तुलना में वित्तीय निष्पादन की सभी दृष्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य सहकारी बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 2013-14 में 5.5 प्रतिशत था जो और घटकर 2014-15 में 5.0 प्रतिशत रह गया, जबकि उनका वसूली अनुपात 2013-14 के 82.5 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 94.9 प्रतिशत हो गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में थोड़ी कमी आई (2013-14 में 10.3 प्रतिशत जबकि 2014-15 में 9.5 प्रतिशत) किंतु उनका वसूली अनुपात 2013-14 के 78.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 77.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.2)।

3.20 2014-15 के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में स्थित राज्य सहकारी बैंक के लाभ में वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में हुई, जहां पर 2014-15 में लाभ में वृद्धि 2013-14 की तुलना में लगभग चार गुना रही। मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में स्थित राज्य सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट आई अथवा वे स्थिर बने रहे। सर्वाधिक गिरावट (2.6 प्रतिशत बिंदु) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देखी गई। मांग के प्रतिशत के रूप में वसूली से मिलेजुले रुझान का पता चला, जिसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में बदलाव देखा गया जहां पर मांग की तुलना में वसूली अनुपात 2013-14 के 58 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़कर 2014-15 में 94.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उस क्षेत्र के रुझान के स्तर से अधिक रही (लगभग 90 प्रतिशत)।

सारणी 3.2 : ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (अल्पावधि)

(₹ बिलियन)

मद	राज्य सहकारी बैंक				जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक			
	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़		मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	57.0	57.2	1.2	0.4	209.0	208.0	15.8	-0.5
i. अवमानक	20.7	20.8	0.3	0.5	100.2	93.2	27.3	-7.0
	(36.2)	(36.3)			(47.9)	(44.8)		
ii. संदिग्ध	26.1	24.7	31.2	-5.4	86.9	91.1	14.0	4.8
	(45.9)	(43.2)			(41.6)	(43.8)		
iii. नुकसान	10.2	11.7	-35.4	15.0	21.9	23.7	-14.4	8.3
	(17.9)	(20.5)			(10.5)	(11.4)		
आ. ऋण की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	5.5	5.0			10.3	9.5		
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%) (विगत वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार)	82.5	94.9			78.3	77.3		

टिप्पणियां : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं । अ : अनंतिम
स्रोत : नाबाई

3.21 जिला स्तर पर, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर, वृद्धि हुई। मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हुई वृद्धि मामूली ही रही। 2014-15 में, दक्षिणी क्षेत्र के साथ ही मध्यवर्ती क्षेत्र में भी मांग की तुलना में वसूली अनुपात में गिरावट आई। दक्षिणी क्षेत्र में वसूली में गिरावट का रुझान जारी रहा (2012-13 में 90.9 प्रतिशत, 2013-14 में 81.3 प्रतिशत एवं 2014-15 में 75.9 प्रतिशत)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां

3.22 बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए जाने में काफी प्रगति हुई है। नवंबर 2014 में, केंद्र सरकार द्वारा घोषित पुनरुद्धार योजना को लागू किए जाने के बाद बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। सितंबर 2016 के अंत में, यह संख्या 23 से घटकर मात्र 3 रह गई।

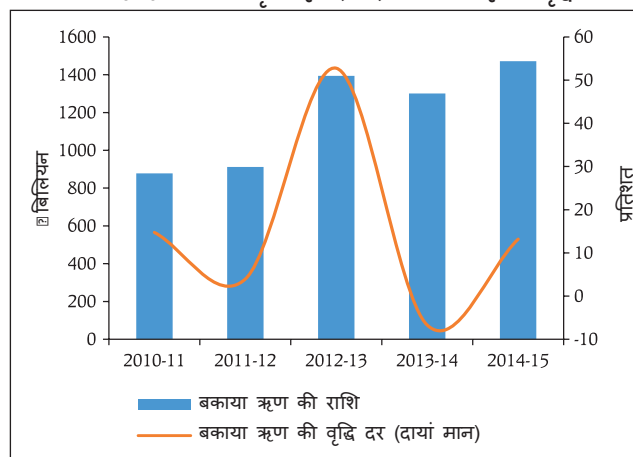
प्राथमिक कृषि समितियां (पीएसीएस)

3.23 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में, 2013-14 के दौरान मंदी के बाद, 2014-15 के दौरान तेजी नजर आई (चार्ट 3.15)।

3.24 सदस्यों की तुलना में उधारकर्ताओं के समग्र अनुपात में 2013-14 के दौरान के स्तर की तुलना में सुधार हुआ। यह अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से दिए जाने वाले ऋण की तुलना में उपलब्धता का उपयोगी संकेतक है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अधिकांश सदस्य लघु एवं सीमांत किसान ही बने रहे, किंतु सदस्य की तुलना में उधारकर्ता के समग्र अनुपात में वृद्धि होने में 'ग्रामीण कारीगरों' द्वारा ऋण की तुलना में उपलब्धता में हुई वृद्धि का काफी योगदान रहा (चार्ट 3.16)।

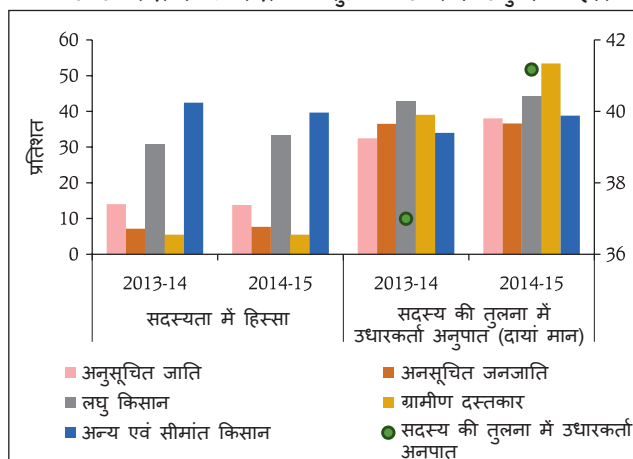
3.25 लाभ कमाने और घाटे में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में, 2013-14 के स्तर की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (चार्ट 3.17)। पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सबसे कमजोर निष्पादन वाले क्षेत्र बने रहे, जहां पर घाटे में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण

चार्ट 3.15 : प्राथमिक कृषि ऋण समिति के बकाया ऋण में वृद्धि



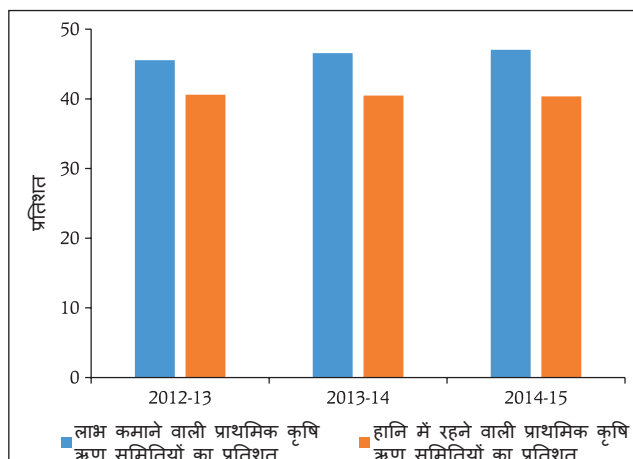
स्रोत : एनएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.16 : सदस्यता एवं सदस्यों की तुलना में उधारकर्ता अनुपात में हिस्सा



स्रोत : एनएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.17 : लाभ एवं हानि में प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्रतिशत (अखिल भारतीय)



स्रोत : एनएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

समितियों की संख्या लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से अधिक रही (चार्ट 3.18)। मध्यवर्ती एवं उत्तरी क्षेत्र सबसे मजबूत क्षेत्रों के रूप में उभरे, जहां पर लाभ में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या घाटे में रहने वाली समितियों से काफी अधिक रही।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण

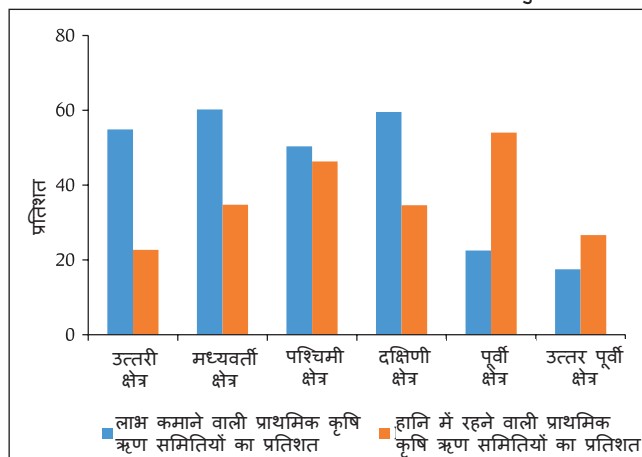
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

3.26 2014-15 में, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन पत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में यह वृद्धि 0.7 प्रतिशत थी। देयता पक्ष में, प्रमुख योगदान उधार राशियों एवं अन्य देयताओं का रहा जबकि आस्ति पक्ष में हुई अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि में निवेशों, अन्य आस्तियों तथा ऋणों और अग्रिमों का योगदान रहा। 2014-15 में ब्याज से होने वाली आय में गिरावट आई और इसलिए कुल आय वृद्धि में कमी हुई। तब भी, 2014-15 में निवल हानि में कमी आई क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक परिचालनगत व्ययों के कारण परिचालनगत लाभ में कमी आई। 2014-15 के दौरान आकस्मिकताओं के प्रति किए गए प्रावधानों के 28.9 प्रतिशत कम रहने के कारण ऐसा हुआ।

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

3.27 2014-15 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन पत्रों में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2013-14 में हुई 3.3 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक

चार्ट 3.18 : लाभ एवं हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत - क्षेत्रीय स्तर (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

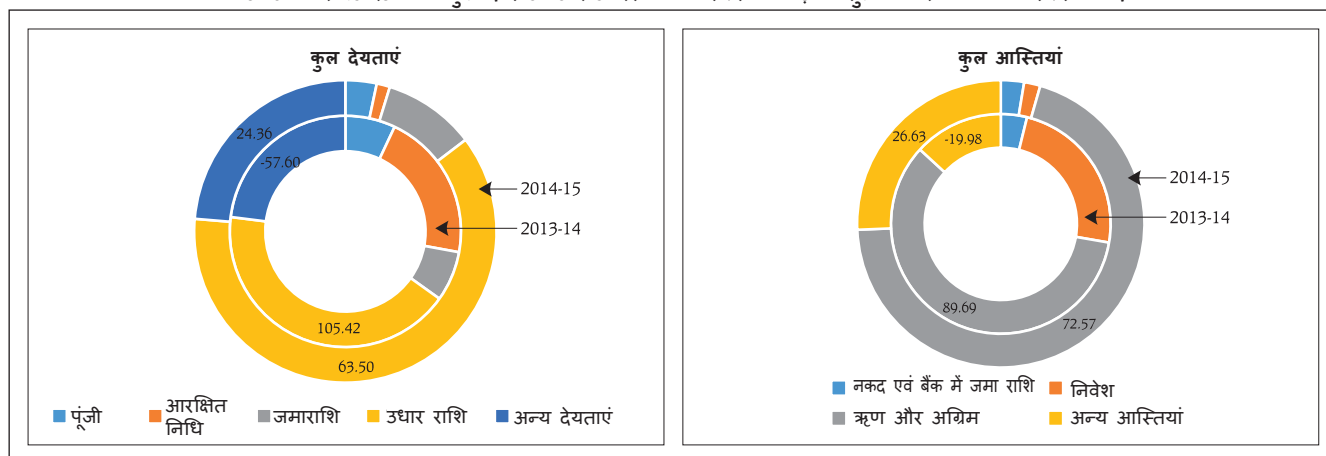


स्रोत : नाबार्ड एनएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

रही। इसका मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों, अन्य आस्तियों (2013-14 में -1.4 प्रतिशत, 2014-15 में 2.8 प्रतिशत) तथा अन्य देयताओं (2013-14 में -6.7 प्रतिशत, 2014-15 में 4.4 प्रतिशत) में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होना और उधार राशियों में मजबूती से वृद्धि होना रहा (चार्ट 3.19)।

3.28 2014-15 के दौरान, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के नुकसान में वृद्धि हुई क्योंकि व्यय वृद्धि आय वृद्धि से अधिक रही। व्यय की सभी मदों के अंतर्गत वृद्धि में तेजी देखी गई जबकि ब्याज से होने वाली आय में 2014-15 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं 2013-14 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

चार्ट 3.19 : पीसीएआरडीबी की कुल देयताओं और आस्तियों में प्रतिशत घट-बढ़ की तुलना में संघटकों का प्रतिशत योगदान



स्रोत : नाबार्ड

3.29 2014-15 में, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण संस्थानों का आस्ति गुणवत्ता एवं वसूली से संबंधित निष्पादन, विशेष रूप से राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के निष्पादन में सुधार हुआ। 2013-14 एवं 2014-15 के बीच राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 35.6 प्रतिशत से गिरकर 30.3 प्रतिशत रह गया और वसूली अनुपात में 33.2 प्रतिशत से 46.7

प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 2013-14 में 37.3 प्रतिशत था जो घट कर 2014-15 में 36.2 प्रतिशत रह गया और मांग की तुलना में वसूली अनुपात में सुधार जारी रहा (2012-13 में 42.7 प्रतिशत, 2013-14 में 43.9 प्रतिशत और 2014-15 में 44.6 प्रतिशत) (सारणी 3.3)।

सारणी 3.3 : ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (दीर्घावधि)

(₹ बिलियन)

मद	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक				प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक			
	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़		मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2014	2015 अ	2013-14	2014-15अ	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	72.6	64.4	7.5	-11.3	48.1	53.6	-0.3	11.5
i. अवमानक	31.05 (42.8)	24.6 (38.1)	10.3	-20.9	22.1 (46.0)	27.3 (50.9)	-0.6	23.6
ii. संदिग्ध	41.4 (57.0)	39.2 (60.9)	8.7	-5.2	25.6 (53.3)	26.0 (48.5)	-0.04	1.4
iii. हानि	0.1 (0.2)	0.6 (0.9)	-91.1	445.5	0.4 (0.8)	0.3 (0.6)	-2.6	-13.5
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का सकल अनुपात (%)	35.6	30.3			37.3	36.2		
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%) (विगत वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार)	33.3	46.7			43.9	44.6		

टिप्पणियां : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं।
स्रोत : नाबार्ड

अ : अंतिम